

## गवर्नर का वक्तव्य\*

### शक्तिकांत दास

दो वर्ष पहले मार्च 2020 में, हमने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के हमले से लड़ने के लिए एक यात्रा शुरू की। उसके बाद की अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अशांत स्थितियों में अपने मार्ग को सफलतापूर्वक प्रशस्त किया है। जबकि महामारी ने हमारी मानसिकता को डरा दिया है और हमारे लचीलेपन का परीक्षण किया है, हमने महामारी की तीन लहरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए साहसिक, अपरंपरागत और दृढ़ उपायों के साथ प्रतिक्रिया दी है। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, हमने यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कार्य फुर्तीले और सक्रिय लेकिन अच्छी तरह से समय पर हों, चलनिधि की स्थिति को पुनर्संतुलित करने की दिशा में उपाय किए हैं।

अब दो वर्ष बाद, जब हम महामारी की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 24 फरवरी से यूरोप में युद्ध की शुरुआत के साथ, प्रतिबंधों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के साथ विवर्तनिक बदलाव देखा है। हम नई लेकिन भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं - प्रमुख वस्तुओं की कमी; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में फ्रैक्चर; और अवैश्वीकरण का डरा। अत्यधिक अस्थिरता पण्य और वित्तीय बाजारों की विशेषता है। जबकि महामारी तेजी से स्वास्थ्य संकट से जीवन और आजीविका में बदल गई, यूरोप के संघर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की क्षमता है। कई विपरीत परिस्थितियों के बीच फंसे होने के बावजूद, हमारे दृष्टिकोण को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन भारत की वृद्धि, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। हालाँकि, हम पिछले कुछ वर्षों में निर्मित मजबूत बफर्स से आश्वस्त हैं, जिसमें बड़े विदेशी मुद्रा भंडार, बाहरी क्षेत्र के संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार और वित्तीय क्षेत्र की पर्याप्त मजबूती शामिल हैं, और ये सभी हमें इस तूफान का सामना करने में मदद करेंगे। एक बार फिर, हम

आरबीआई में अर्थव्यवस्था की रक्षा करने और मौजूदा तूफान से बाहर निकलने के लिए दृढ़ और तत्पर हैं।

### मौद्रिक नीति समिति के निर्णय और विचार-विमर्श

इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 6, 7 और 8 अप्रैल 2022 को बैठक हुई और समष्टि आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण के आकलन के आधार पर, नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि निभावकारी को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 आधार अंकों तक बहाल किया जाए, जो कि महामारी से पहले की स्थिति थी। कॉरिडोर का आधार अब नई स्थापित स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसे रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे, अर्थात् 3.75 प्रतिशत पर रखा जाएगा। मैं इस बारे में बाद में अपने वक्तव्य में बताऊंगा।

मैं सबसे पहले नीतिगत दर और रुख पर एमपीसी के निर्णय के औचित्य पर ध्यान देना चाहूंगा। फरवरी 2022 की शुरुआत में एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से, ओमीक्रोन लहर में उतार-चढ़ाव से अपेक्षित सकारात्मक लाभ भू-राजनीतिक तनावों में तेज वृद्धि से ऑफसेट हो गए हैं। इससे बाहरी और घरेलू परिदृश्य महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है। तेल और प्राकृतिक गैस; गेहूं और मक्का; पैलेडियम, एल्यूमीनियम और निकल; खाद्य तेल; और उर्वरक जैसी प्रमुख वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन और निर्यात में युद्ध में लगी दो अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण हिस्से को देखते हुए, लंबी आपूर्ति व्यवधानों पर चिंताओं ने वैश्विक कमोडिटी और वित्तीय बाजारों को हिला दिया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय के लिए 130 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गईं, जो 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर को छू रही हैं और कुछ सुधारों के बावजूद ऊंचे स्तर पर अस्थिर बनी हुई हैं। धातु और अन्य कमोडिटी की कीमतों के साथ वैश्विक खाद्य कीमतों में भी काफी तेजी आई है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई)

\* गवर्नर का वक्तव्य : 8 अप्रैल 2022

की परिसंपत्तियों के प्रति जोखिम निवारण में वृद्धि हुई है, जिससे बड़ी पूंजी बहिर्वाह और उनकी मुद्राओं में मूल्यहास पूर्वाग्रह हो गया है। इन घटनाओं ने, सबसे पहले, वैश्विक मुद्रास्फीति के अनुमानों को तेज किया है, जो पहले से ही प्रमुख देशों में लक्ष्य से काफी ऊपर चल रहा था; और दूसरा, भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करेगा।

भू-राजनीतिक तनाव ऐसे समय में बढ़ गया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि और प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से जूझ रही थी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और इनपुट लागत दबाव अब और भी लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद है। मार्च में कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमणों का फिर से उभरना और संबंधित लॉकडाउन, वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और इनपुट लागत दबावों को और बढ़ाने का जोखिम उठा रहे हैं। विश्व व्यापार और उत्पादन और इसलिए बाहरी मांग दो महीने पहले की परिकल्पना की तुलना में कमजोर होने की संभावना है। कुल मिलाकर, पिछले दो महीनों के दौरान बाहरी विकास ने घरेलू विकास के दृष्टिकोण के लिए अधोगामी जोखिम और फरवरी एमपीसी प्रस्ताव में प्रस्तुत मुद्रास्फीति अनुमानों के लिए अपसाइड जोखिम को बढ़ा दिया है। मुद्रास्फीति अब फरवरी में मूल्यांकन की तुलना में अधिक और विकास दर कम रहने का अनुमान है। आर्थिक गतिविधि, हालांकि ठीक हो रही है, अपने पूर्व-महामारी स्तर से मुश्किल से ऊपर है। इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभावकारी रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निभावकारी बने रहने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति आगे लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

## विकास और मुद्रास्फीति का आकलन

### संवृद्धि

28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी खपत और निश्चित निवेश - घरेलू मांग के प्रमुख चालक

- हालांकि, इन दो घटकों के साथ, उनके पूर्व-महामारी के स्तर क्रमशः केवल 1.2 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत से कम रहे। आपूर्ति पक्ष पर, संपर्क-गहन सेवाएं अभी भी 2019-20 के स्तर से पीछे हैं। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने महामारी प्रेरित संकुचन से लगातार उबर रही है।

2021-22 के दौरान, तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी फिर से उभरी और जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन वेरियंट के उभरने से और तेज हो गई। फरवरी के दौरान एक क्रमिक बदलाव देखा गया है, हालांकि मार्च 2022 में एक मिश्रित तस्वीर देखी गई थी। घटते संक्रमण और प्रतिबंधों को हटाने के बीच कुछ संपर्क-गहन गतिविधियों ने कर्षण प्राप्त कर लिया है। कई उच्च आवृत्ति संकेतक - रेलवे माल ढुलाई; जीएसटी संग्रह; टोल संग्रह; बिजली की मांग; ईंधन की खपत; और पूंजीगत वस्तुओं के आयात ने फरवरी-मार्च के दौरान वर्ष -दर-वर्ष मजबूत विस्तार दर्ज किया। प्रतिबंधों में ढील के साथ, घरेलू हवाई यात्री यातायात मार्च में फिर से शुरू हो गया। हमारे सर्वेक्षणों के अनुसार, उपभोक्ता विश्वास में सुधार हो रहा है और आने वाले वर्ष के लिए परिवारों की आशावाद भावनाओं में तेजी के साथ मजबूती आई है। व्यावसायिक विश्वास आशावादी क्षेत्र में है और आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार का समर्थन करता है। दूसरी ओर, यात्री वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में गिरावट जारी है, हालांकि मध्यम गति से। विनिर्माण और सेवाएं पीएमआई दोनों ही विस्तार के क्षेत्र में बने हुए हैं; जबकि मार्च में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में थोड़ी नरमी आई, सेवाओं और कंपोजिट में सुधार दर्शाया गया।

आगे चलकर, मजबूत रबी उत्पादन से ग्रामीण मांग में सुधार का समर्थन करना चाहिए, जबकि संपर्क-गहन सेवाओं में तेजी से शहरी मांग को और मजबूत करने में मदद मिलनी चाहिए। कारोबार विश्वास में सुधार, बैंक ऋण में वृद्धि, सरकारी पूंजीगत व्यय से निरंतर समर्थन और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के कारण निवेश गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पिछली तिमाही के 68.3 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 की तीसरी तिमाही में 72.4 प्रतिशत हो गया, जो 2019-20 की चौथी तिमाही में 69.9 प्रतिशत के महामारी के पहले के स्तर को पार कर गया।

जैसे ही होरीज़ोन में सुधार हुआ था, बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने हमारे आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित किया है। यद्यपि, युद्ध के केंद्र में स्थित देशों के साथ भारत का प्रत्यक्ष व्यापार एक्सपोजर सीमित है, युद्ध संभावित रूप से कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक स्पिलओवर चैनलों के माध्यम से आर्थिक सुधार को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण से प्रेरित वित्तीय बाजार की अस्थिरता, कुछ प्रमुख देशों में नए सिरों से कोविड-19 संक्रमणों के साथ बढ़ी हुई आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों और महत्वपूर्ण इनपुट, जैसे कि सेमी-कंडक्टर और चिप्स, की भारी कमी ने संभावनाओं के लिए अधोगामी जोखिम उत्पन्न किया है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और 2022-23 में कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल होने के अनुमान पर, 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब 7.2 प्रतिशत पर अनुमानित है, जोकि पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

### मुद्रास्फीति

एमपीसी की फरवरी 2022 की बैठक ने 2022-23 के दौरान मुद्रास्फीति के लिए एक मॉडरेटिंग पथ का अनुमान लगाया था। हालांकि, फरवरी के अंत से बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनावों ने पहले के आख्यान को बदल दिया है और वर्ष के लिए मुद्रास्फीति संभावनाओं को काफी हद तक धूमिल कर दिया है। खाद्य कीमतों के मोर्चे पर, एक संभावित रिकॉर्ड रबी फसल, अनाज और दालों की घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी। हालांकि, काला सागर क्षेत्र से गेहूं की आपूर्ति में कमी और गेहूं की अभूतपूर्व उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों जैसे वैश्विक कारक घरेलू गेहूं की कीमतों को प्रभावित किया है। प्रमुख उत्पादकों द्वारा निर्यात प्रतिबंधों के साथ-साथ काला सागर क्षेत्र से आपूर्ति में कमी के कारण खाद्य तेल की कीमतों का दबाव निकटावधि में उच्च बने रहने की संभावना है। वैश्विक आपूर्ति की कमी के कारण फ़ीड लागत दबाव जारी रह सकता है, जिसका पॉल्ट्री, दूध और डेयरी उत्पाद की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

खाद्येतर पदार्थों की बात करें तो, फरवरी के अंत से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी ने प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों के माध्यम से मुद्रास्फीति के लिए पर्याप्त सकारात्मक जोखिम पैदा किया है। घरेलू पंपों की कीमतों में तेज वृद्धि, वैविध्यपूर्ण दूसरे दौर के मूल्य दबावों को ट्रिगर कर सकती है। उच्च अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों और बढ़े हुए लॉजिस्टिक व्यवधानों का संयोजन, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में इनपुट लागत को बढ़ा सकता है। इसलिए, खुदरा कीमतों के लिए उनके प्रभाव अंतरण से निरंतर निगरानी और सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन आवश्यक है। बढ़ते जोखिम प्रीमियम, व्यापार और पूंजी प्रवाह में अव्यवस्था और सभी केंद्रीय बैंकों में भिन्न मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं के कारण वित्तीय बाजारों के अस्थिर रहने की संभावना है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और 2022 में सामान्य मानसून और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल होने के अनुमान पर, मुद्रास्फीति अब 2022-23 में 5.7 प्रतिशत पर अनुमानित है, जिसमें पहली तिमाही में 6.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.8 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.1 प्रतिशत पर रहने के अनुमान है।

हालांकि, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि फरवरी के अंत से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता और उभरती भू-राजनीतिक तनावों पर अत्यधिक अनिश्चितता को देखते हुए, संवृद्धि और मुद्रास्फीति का कोई भी अनुमान जोखिम भरा है, और काफी हद तक भविष्य में तेल और कमोडिटी की कीमतों के विकास पर निर्भर है।

इस संदर्भ में, आपूर्ति पक्ष के उपायों की निरंतरता और गहनता, खाद्य मूल्य दबाव को कम कर सकता है और विनिर्माण और सेवाओं में लागत-प्रेरित दबाव को भी कम कर सकता है। हमारी ओर से, मैं सभी हितधारकों को आश्वस्त करता हूँ कि पहले की तरह, रिज़र्व बैंक अपनी सभी नीतिगत लीवर का उपयोग समष्टि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और हमारी अर्थव्यवस्था की आघात सहनीयता को बढ़ाने के लिए करेगा। स्थिति गतिशील और तेजी से बदल रही है और हमें भी उसी अनुरूप कार्य करने होंगे।

### चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समष्टि आर्थिक संभावनाएं विवर्तनिक (tectonic) बदलावों के दौर से गुजर रहा है और हमारी नीतिगत प्रतिक्रिया प्रारंभिक होनी चाहिए और उभरती

संभावनाओं के लिए गतिशील रूप से पुनः कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखते हुए चलनिधि प्रबंधन के लिए एक सूक्ष्म और त्वरित दृष्टिकोण अपनाना जारी रखेगा। वर्तमान में, चलनिधि प्रबंधन को दो-तरफ़ा संचालन: चलनिधि को अवशोषित करने के लिए भिन्न परिपक्वता वाले परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर); और नीलामी क्षणिक चलनिधि की कमी और ऑफसेट बेमेल को पूरा करने के लिए परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) के माध्यम से, चित्रित किया जाता है। यह तरीका जारी रहेगा।

इस बात पर ध्यान दिया जाए कि 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान एलएएफ़ के तहत अवशोषित कुल चलनिधि के लगभग 80 प्रतिशत के लिए ब्याज दर वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से चलनिधि के पुनर्संतुलन के कारण नीतिगत रेपो दर के करीब पहुंच गई है। तदनुसार, वित्तीय बाजार सहभागियों को एलएएफ़ कॉरिडोर के संभावित सामान्यीकरण के लिए तैयार किया गया है।

इसके अलावा, अब फरवरी 2020 में स्थापित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को, यद्यपि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ सुधारों के साथ, पूरी तरह से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित उपाय स्थापित किए जा रहे हैं:

- i. 2018 में आरबीआई अधिनियम की धारा 17 में संशोधन ने रिज़र्व बैंक को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) शुरू करने का अधिकार प्रदान किया। केंद्रीय बैंक पर बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को हटाकर, एसडीएफ मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत बनाता है। तदनुसार, अब एसडीएफ को एलएएफ़ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह कॉरिडोर के शीर्ष पर स्थित अंतर्वेशन उपकरण, अर्थात् सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के समान, एलएएफ़ कॉरिडोर के निचले भाग में एक स्थायी अवशोषण सुविधा शुरू करके मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को समरूपता प्रदान करेगा। इस प्रकार, एलएएफ़ कॉरिडोर के दोनों सिरों पर स्थायी सुविधाएं होंगी - एक चलनिधि को अवशोषित करने के लिए और दूसरी अंतर्वेशित करने के लिए। तदनुसार, एसडीएफ और एमएसएफ तक पहुंच बैंकों के विवेक पर आधारित

होगी। यह रेपो/रिवर्स रेपो, ओएमओ और सीआरआर के विपरीत है, जो रिज़र्व बैंक के विवेक पर उपलब्ध हैं। विशेष रूप से, चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता उपकरण भी है।

- ii. एसडीएफ दर, नीतिगत दर से 25 बीपीएस कम होगी, और यह इस स्तर पर एक दिन की जमाराशियों पर लागू होगी। तथापि, यह उचित मूल्य निर्धारण के साथ, आवश्यकता पड़ने पर, लंबी अवधि की चलनिधि को अवशोषित करने के लचीलेपन को बनाए रखेगा। एमएसएफ दर, नीतिगत रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार, एलएएफ़ कॉरिडोर के आयाम को पूर्व-महामारी विन्यास में 50 बीपीएस पर पुनःस्थापित किया जाता है, जो संतुलित रूप से नीतिगत रेपो दर के आसपास, कॉरिडोर के केंद्र में होगा।
- iii. स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो (एफ़आरआरआर) दर को 3.35 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। यह आरबीआई के टूलकिट के भाग के रूप में रहेगा और इसका परिचालन समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आरबीआई के विवेक पर होगा। एसडीएफ के साथ एफ़आरआरआर आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन ढांचे को लचीलापन प्रदान करेगा।
- iv. एमएसएफ और एसडीएफ दोनों पूरी वर्ष सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होंगे।
- v. यह भी निर्णय लिया गया है कि 18 अप्रैल 2022 से आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के खुलने का समय, पूर्व-महामारी समय, सुबह 9:00 बजे से पुनः प्रचलन में लाया जाए, जो वर्तमान में प्रचलित उनके समापन समय में किसी भी बदलाव के बिना है।

महामारी के दौरान, आरबीआई ने ₹17.2 लाख करोड़ के ऑर्डर की चलनिधि सुविधाओं को प्रदान किया, जिसमें से ₹11.9 लाख करोड़ का उपयोग किया गया था। अब तक विभिन्न सुविधाओं की नियत तारीखों पर व्यपगत होने पर ₹5.0 लाख करोड़ वापस कर दिए गए हैं या वापस ले लिए गए हैं। आरबीआई के विभिन्न अन्य परिचलनों के माध्यम से अंतर्वेशित की गई

चलनिधि के साथ-साथ महामारी के मद्देनजर किए गए असाधारण चलनिधि उपायों के परिणामस्वरूप, प्रणाली में ₹8.5 लाख करोड़ के ऑर्डर की चलनिधि की अधिकता हो गई है। आरबीआई इस वर्ष की शुरुआत में गैर-विघटनकारी तरीके से एकाधिक -वर्ष की समय-सीमा में इस चलनिधि का क्रमिक और अंशांकित आहरण करेगा। इसका उद्देश्य प्रणाली में चलनिधि अधिशेष की मात्रा को मौद्रिक नीति के मौजूदा रुख के अनुरूप स्तर पर बहाल करना है। ऐसा करते हुए, मैं अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहूंगा। सरकार के उधार कार्यक्रम को पूरा करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं और इस दिशा में आरबीआई विभिन्न उपकरणों को आवश्यकतानुसार नियोजित करेगा।

### बाहरी क्षेत्र

बिगड़ते वैश्विक आपूर्ति आघातों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहाली की गति धीमी होने के बावजूद, भारत के व्यापारिक निर्यात में 2021-22 में मजबूत वृद्धि हुई, जो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर गया। घरेलू मांग में बहाली के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में तेज वृद्धि से भी आयात में एक मजबूत पलटाव हुआ है और व्यापार और चालू खाता घाटे का विस्तार हुआ है। सेवाओं के निर्यात और आवक विप्रेषणों में निरंतर और मजबूत वृद्धि हमारे अदृश्य खाते शेष राशि को बड़े अधिशेष में रखना जारी रखती है, जो वाणिज्यिक व्यापार घाटे को आंशिक रूप से ऑफसेट करने में मदद करती है। कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद, हम उम्मीद करते हैं कि चालू खाता घाटा धारणीय स्तर पर बना रहेगा जिसे सामान्य पूंजी प्रवाह के साथ वित्तपोषित किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, हमारे बाहरी क्षेत्र के संकेतक सकारात्मक बने हुए हैं और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1 अप्रैल 2022 को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 606.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो आरबीआई की निवल वायदा आस्तियों से और अधिक मजबूत हुआ है। रिज़र्व बैंक घरेलू वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वैश्विक घटनाक्रम के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, आवश्यकतानुसार, उचित कदम उठाएगा।

### अतिरिक्त उपाय

अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करना चाहता हूँ, जिनका विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों (भाग-बी) के विवरण में दिया गया है। ये उपाय इस प्रकार हैं:

### व्यक्तिगत आवास ऋण - जोखिम भार को युक्तिसंगत बनाना

31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी नए आवास ऋणों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए जोखिम भार को अक्टूबर 2020 में केवल ऋण से मूल्य (एलटीवी) अनुपात के साथ जोड़कर युक्तिसंगत बनाया गया था। आवास क्षेत्र के महत्व और इसके गुणज प्रभावों को स्वीकार करते हुए, इन दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे व्यक्तिगत आवास ऋण के लिए उच्च ऋण प्रवाह की सुविधा होगी।

### एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्तमान सीमा को 31 मार्च 2023 तक एनडीटीएल के 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच पात्र एसएलआर प्रतिभूतियों को इस बढ़ी हुई सीमा के तहत शामिल करने की अनुमति दी जाए। एचटीएम की सीमा 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से 23 प्रतिशत से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी।

### जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर चर्चा पत्र

जलवायु परिवर्तन से कुछ जोखिम पैदा होते हैं जो वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा और सुदृढ़ता और साथ ही वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ हो सकते हैं। विनियमित संस्थाओं द्वारा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संभावित प्रभाव की बेहतर समझ और मूल्यांकन प्रदान करने के लिए, जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र शीघ्र ही फीडबैक हेतु प्रकाशित किया जाएगा।

## आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए समिति

रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्षों में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में ग्राहक सेवा, आंतरिक शिकायत निवारण और लोकपाल तंत्र पर विनियामक ढांचा तैयार करना शामिल है। उत्पादों और सेवाओं में नवोन्मेष, डिजिटल पहुंच में वृद्धि और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उद्भव के कारण वित्तीय परिदृश्य में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए, आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की वर्तमान स्थिति की जांच और समीक्षा करने के लिए तथा ग्राहक सेवा विनियमों की पर्याप्तता और उनमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

## एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी

वर्तमान में एटीएम से कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा कुछ ही बैंकों तक सीमित है। अब यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्ड-रहित नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। लेन-देन में आसानी को बढ़ाने के अलावा, ऐसे लेनदेन के लिए भौतिक कार्ड की आवश्यकता न रहने से कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग आदि जैसे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

## भारत बिल भुगतान प्रणाली - परिचालन इकाइयों के लिए निवल मालियत की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाना

बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) में पिछले कुछ वर्षों में बिल भुगतान और बिल बनाने वालों (बिलर्स) की मात्रा में वृद्धि हुई है। बीबीपीएस के माध्यम से बिल भुगतान की पहुंच को और सुगम बनाने के लिए और बीबीपीएस में अधिक संख्या में गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी संस्थाओं की निवल संपत्ति की आवश्यकता को ₹100 करोड़ से घटाकर ₹25 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

## भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स (पीएसओ) की साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में भुगतान प्रणाली एक उत्प्रेरक भूमिका निभाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी भुगतान प्रणालियां पारंपरिक और उभरते जोखिमों, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों के प्रति आघात-सहनीयता बनी रहें, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स के लिए साइबर आघात-सहनीयता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

## समापन टिप्पणी

पिछले दो वर्षों में बहुत ज्यादा अशांति और अनिश्चितता देखी गई है। रिज़र्व बैंक में, हमने अपनी अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए अथक प्रयास किया है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमने स्पष्टवादिता, साहस और इस विश्वास के साथ एक कठिन रास्ता तय किया है और आगे एक उज्ज्वल भविष्य है।

यूरोप में संघर्ष अब एक नई और बड़ी चुनौती बन गया है, जो पहले से ही अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य को जटिल बना रहा है। जैसा कि भू-राजनीतिक स्थिति की मुश्किलों ने हमें चुनौती दी है, आरबीआई अपने नियंत्रण में सभी उपकरणों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए तैयार है। जैसा कि हमने पिछले दो वर्षों में प्रदर्शित किया है, हम किसी भी नियम पुस्तिका के बंधक नहीं हैं और जब अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की बात आती है तो कोई कार्रवाई ऑफ दि टेबल नहीं है। कीमत स्थिरता, निरंतर विकास और वित्तीय स्थिरता के हमारे लक्ष्य पारस्परिक रूप से मजबूत हैं और हम इस दृष्टिकोण से निर्देशित होते रहेंगे।

वर्तमान समय में आसमान में भले ही अनिश्चितता के बादल छाये हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी सारी ऊर्जा, संकल्प और संसाधनों का उपयोग सूर्य के प्रकाश को भारत के भविष्य को रोशन करने के लिए करेंगे। मैं अपनी बात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले जो कहा था, उसे याद करते हुए समाप्त करता हूँ: “यह विश्वास ही है जो हमें तूफानी समुद्रों में मार्गदर्शित करता है, विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिलाता है और विश्वास ही है जो समुद्र पार कराता है।”<sup>1</sup>

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

<sup>1</sup> यंग इंडिया, 24-9-1925, पृष्ठ 331